

फूड सेक्टर के प्रतिनिधियों ने खाद्य उत्पादों पर एफओपीएल चेतावनी पर दिया बल



» मद्रास संवाददाता

गुरुग्राम। हैल्थी फूड के प्रति उपभोक्ताओं में जागृकता फैलाने की दिशा में कोलकाता में सम्पन्न हुई स्ट्रेटिजिक प्लानिंग मीट में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे सिटिजंस अवेरनेस ग्रुप (सीएजी) और स्थानीय उद्योग के प्रतिनिधियों का मत था कि भारत में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप हार्फ्रेट आफ पैक लैबलिंग (एफओपीएल) का अनुसरण होना आवश्यक है। सीएजी के चैयरमैन सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि इस मीट में देश भर से फूड सेक्टर के स्टैकहोल्डर्स जुटे और इस दिशा में उठाये जाने वाले प्रयासों को कैसे प्रभावी बनाया जाये, उन सभी पहलुओं पर चिंतन मंथन किया। मीट के दौरान फूड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ इस दिशा में प्रयासरत संगठन और एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों की भी व्यापक भागीदारी देखने की मिली। मीट के आयोजक व कंचुमार

वायस के सीईओ अशीम सन्याल ने बताया कि देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की खपत में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने के साथ भारत, एफओपीएल को अपनाने को प्राथमिकता दे रहा। भारत ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजिस की सेल और खपत में उच्चतम दर दर्ज की है। यह प्रोडक्ट्स चीनी, नमक और एडिटिव्स में बहुत युक्त होते हैं। 2006-2019 के यूरोमीटर सेल्स डाटा के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पैकेज्ड जंक फूड और बेवरेजिस सेक्टर मात्र 13 सालों में ही 42 गुणा बढ़ गया है जिसकी अन्देखी खपत चिंता का कारण है। इसके विपरीत सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का रोजगार सृजन के लिये एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखती है, वर्तमान में यह मार्केट 200 बिलियन डालर्स का है और भविष्य में यह 500 बिलियन डालर्स तक बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस तेजी से पनप रहे सेक्टर के लिये एफओपीएल

जैसे मापदंड जल्द लागू किये जाने चाहिये जिससे की उद्योग भी प्रभावित न हो और खपतकार लोगों के उनको हैल्थ के प्रति भी सजग रखा जा सके।

मीट में भाग ले रहे ऐसोचैम के उपाध्यक्ष मनीश अग्रवाल का मत था कि इंडियन फूड एमएसएमई के लिये एक बड़ा लक्ष्य पारंपरिक भोजन के हैल्थी वर्जन को अपनाना है जो वैश्विक निर्यात के अनुरूप है। इससे निर्यात के लिये एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। उनके अनुसार एफओपीएल के अनुरूप भारत, पारंपरिक स्नैक्स के लिये एक बड़ा बाजार विकसित कर सकता है।

मीट के दौरान यह निष्कर्ष उभर कर आया कि वर्ष 2030 तक भारतीय उपभोक्ता प्रोसेस्ड और ब्रांडेड फूड उत्पादों में लगभग छह ट्रिलियन डालर्स खपत करेगा जिस पर एक चेतावनी रुपी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। एफओपीएल के तत्काल लक्ष्य संभव होगा।

